

दूसरों को अपने सपने साकार करने में मदद करें, आप भी अपने लक्ष्य हासिल कर लें...
-लेस ब्राउन



निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

प्रवाह

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आईएल एंड एफएस के डूबने से अब पीएफ और पेंशन के मद में 20,000 करोड़ रुपये के डूबने की बात कही जा रही है। यानी संस्थाओं की लापरवाही के कारण लाखों वेंतनभोगियों की मेहनत की कमाई के डूबने की आशंका है।

एनबीएफसी पर नकेल कसें

सरकारी क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आईएल एंड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज) के डूबने से सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं पर असर पड़ने के अलावा बैंकों और शेयर बाजार में हड़कंप तो पहले ही मच गया था, अब इसके कारण वेंतनभोगियों के पीएफ और पेंशन के करोड़ों रुपये डूबने की आशंका जताई जा रही है। आम आदमी की मेहनत की कमाई का पैसा डूबने की आशंका बेहद गंभीर है। आईएल एंड एफएस के दिवालिया होने के मूल में जाएं, तो पता चलता है कि तमाम जिम्मेदार संस्थाओं की लापरवाही के कारण यह स्थिति आई। जबकि आईएल एंड एफएस के संकट को शुरुआत से ही अमेरिका में लेहमान ब्रदर्स के

दिवालिया होने जैसा गंभीर बताया जा रहा था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है, लेकिन वह इसके संकट को भांप नहीं पाया और इसे कर्ज देने का सिलसिला जारी रहा। जब यह कंपनी डूबने लगी, तब सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को इसे संकट से निकालने के लिए लगाया, लेकिन समाधान नहीं निकला। रेटिंग देने वाली एजेंसियों ने तो हद दर्ज की लापरवाही का परिचय दिया। आईएल एंड एफएस के वित्तीय संकट को भांप पाना तो दूर, उन्होंने अंत तक इस कंपनी की 'एएए' रेटिंग जारी रखी, जो निवेश के लिहाज से उच्चतम श्रेणी है। इस रेटिंग के आधार पर ही अनेक कंपनियों ने, जो अपने कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन का प्रबंधन खुद करती हैं, आईएल एंड एफएस के बॉन्ड्स खरीदे तथा उसे कर्ज दिए। पर

कर्ज न चुका पाने के एक सप्ताह के भीतर ही रेटिंग एजेंसियों ने आईएल एंड एफएस की रेटिंग 'एएए' से जंक (कबाड़) कर दी। अंकड़ों के मुताबिक, वेंतनभोगियों के पीएफ और पेंशन के 20,000 करोड़ रुपये डूबने के कगार पर हैं। यह रकम बैंकों, म्यूचुअल फंडों और अन्य योजनाओं के जरिये इस इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी को मिले कर्ज से इतर है। हालांकि नियम के मुताबिक, उन निजी कंपनियों को इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इंपीएफओ इस शर्त पर ही कंपनियों को पीएफ और पेंशन के प्रबंधन की इजाजत देता है। लिहाजा इस पर तो नजर रखी ही जानी चाहिए कि संस्थाओं की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को न भुगतान पड़े, उम्मीद करनी चाहिए कि यह संकट उन तमाम संस्थाओं को जिम्मेदार होने के लिए भी प्रेरित करेगा।

किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा



कॉरपोरेट घरानों को भारी कर्जमाफी को लेकर आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, जबकि कृषि ऋणों पर अनावश्यक गर्मी पैदा की जाती है।



देविंदर शर्मा, कृषि नीति विशेषज्ञ

परिणामस्वरूप अन्य कल्याणकारी योजनाएं पीछे रह जाएंगी?

हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई 36,359 करोड़ रुपये की कृषि कर्जमाफी योजना थी। अपने जवाब में मैंने कहा कि बेशक हर कर्जदार किसान तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा, फिर भी इस कर्जमाफी से 44 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। यह छोटी संख्या नहीं है और लाभान्वितों की संख्या

आयरलैंड की आबादी से भी ज्यादा है। अब इसकी तुलना वर्ष 2012 से 2014 के बीच मट्टी भर बिजली वितरण कंपनियों को दी गई 72,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से करें और आश्चर्यजनक रूप से तब कर्ज अनुशासनहीनता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया और न ही किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास बिजली वितरण कंपनियों की कर्जमाफी की क्षमता नहीं है। एक अन्य बिजनेस चैनल पर मुझे बताया गया

कि कर्जमाफी एक घातक जहर है। यह वास्तविक मुद्दे को संबोधित करने का एक गलत तरीका है और नैतिक खतरे की ओर ले जाता है। अपने जवाब में मैंने रिजर्व बैंक के दस्तावेज का हवाला दिया, जो कहता है कि अप्रैल, 2014 से अप्रैल, 2018 की चार वर्षों की अवधि में 3.16 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर्ज को बढ़ते खाते में डाला गया। 30 सितंबर को संसद में दिए गए एक अन्य बयान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, केवल 528 उधारकर्ता थे, जिनके पास गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) 6.28 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि उनमें से 95 फीसदी एक हजार करोड़ रुपये के डिफॉल्टर थे। 2.3 लाख करोड़ रुपये की कृषि कर्जमाफी योजना पूरी तरह से लागू होती है, तो अनुमानतः 3.4 करोड़ कृषक परिवारों को फायदा होगा। ऐसे में कॉरपोरेट कर्जमाफी का कोई तुलना नहीं है, जिससे केवल कुछ ही कंपनियों को फायदा होता है। मैंने पूछा कि कैसे कोई संवेदनशील अर्थशास्त्री भारी कॉरपोरेट कर्जमाफी को सही ठहरा सकता है और गरीब किसानों पर निशाना साध सकता है। वास्तव में कॉरपोरेट कर्ज का ढेर बढ़ता जा रहा है। सकल एनपीए 11.2 फीसदी की दर से बढ़कर 2017-18 में 10.39 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है और मात्र 40,400 करोड़ रुपये ही वसूल गए हैं। कॉरपोरेट घरानों को भारी कर्जमाफी को लेकर आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, जबकि कृषि ऋणों पर अनावश्यक गर्मी पैदा की जाती है, जो पूर्वाग्रहपूर्ण आर्थिक सोच को दर्शाती है। हैदराबाद की बात है कि जब भी मैं आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में पिछले 10 वर्षों में उद्योगों को दिए गए 18.60 लाख करोड़ रुपये का सवाल उठाता हूँ, तो एक चुपची जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि वर्ष 2008-09 में सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी के समय उद्योग

के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया था, जो अब भी जारी है और इसके लिए लगातार दस साल भुगतान किया गया है। सरल शब्दों में कहें, तो उद्योग घरानों को हर साल प्रत्यक्ष आय सहायता मिल रही है और किसी ने कभी प्रोत्साहन पैकेज से होने वाली राजकोषीय अनुशासनहीनता पर कोई सवाल नहीं किया है। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि 18.60 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पैसा कहां से आया। अब सातवें वेंतन आयोग को लें। जिस मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा कि इससे सरकार पर प्रति वर्ष 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इससे केंद्र सरकार के 45 लाख कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। अगर इसे पूरे देश में राज्य सरकारों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा, तो कुल वार्षिक बोझ बढ़कर 4.5 से 4.8 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, यह कहना है क्रेडिट सुइस बैंक के अध्यक्ष का। इस पर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं किया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा और न ही किसी ने कहा कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। लेकिन किसानों की कर्जमाफी या अन्य प्रत्यक्ष सहायता पहल की बातें करें, तो राजकोषीय घाटे पर बात करने में मीडिया अति सक्रियता दिखाता है। अमेरिका में जैसा कि एलेक्जेंड्रिया ने बताया, पैसा वहीं से आया, जहां से भारी कॉरपोरेट छूट के लिए पैसा आता है, जहां से रक्षा बजट के लिए आता है, जहां से अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए आता है। भारत में भी किसानों से लिए पैसा उसी स्रोत से आएगा, जहां से सातवें वेंतन आयोग के बजटीय आंकड़ों के लिए आता है, जहां से कॉरपोरेट छूट के लिए आता है और जहां से बड़े पैमाने पर बैंक एनपीए को बढ़ते खाते में डालने के लिए आता है।

अंतर्ध्वनि

संदर्भहीन चीजों को पकड़ने की कोशिश में भी आनंद है

मैं उस पीढ़ी की कवि हूँ, जिसने अरब साहित्य में गद्य कविताओं को हाशिए से उठकर केंद्र में आते हुए देखा है। हालांकि वह वजूद में तो पहले से ही थी। लेकिन निजी तौर पर मैं इराकी गद्य कविता से ज्यादा प्रभावित हुई। इन कवियों को कोई भी अरब कविता समझे या प्रकाशन संस्थाएं मान्यता नहीं देती थीं। हम उनकी कविताओं और अनुवादों की फोटोकॉपी कराकर आपस में बाँटा करते थे। मेरी पीढ़ी के युवा कवि, फिल्मकार और बुद्धिजीवी, हम सब इस अलगाव को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे थे और इसी ने हमें इस इच्छा से भर दिया कि हम अरब संस्कृति के सौंदर्यशास्त्र और ऐतिहासिक विचारधाराओं से परे हट जाएं, कविता में तो खासकर। इस तरह गद्य कविता हमारे लिए मुख्यधारा के महा-आख्यानों का निषेध थी। मसलन युवा कवि के रूप में मैंने अपने पिता और मेरे बीच के जटिल संबंधों को पकड़ने की विफल कोशिशों की थीं, किसी समय मैं उनके भीतर के पुरुष-प्रधान पक्ष की तरफ जाती, तो कभी उनके भीतर के प्रेम और त्याग की तरफ फिसल आती। जब मैंने इन दोनों ही संदर्भों को नकार दिया और फिर से कोशिश की, तो एक तरह से यह मेरे अपने अस्तित्व के साथ एक जुआ खेलने का तरह था, मेरी भाषा, मेरे ज्ञान, मेरे अंधकार के साथ जुआ। लेकिन इसमें आनंद भी है, उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करना, जिनका कोई संदर्भ ही न हो। आपके जुआ खेलने की गंभीरता का जैसा चित्रण दूसरों ने किया है, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप न केवल कुछ रचने की क्रीड़ा और आनंद से भरते होते हैं, बल्कि चीजों और उनके इर्द-गिर्द फैले पूरे सौंदर्यशास्त्र के विखंडन, उन्हें तोड़-मरोड़ देने के अपूर्व सुख को अनुभूत करते हैं।



-मिस की महारू कवयित्री

अमेरिकी संसद के लिए न्यूयॉर्क से चुनी गई युवा सांसद एलेक्जेंड्रिया ओ कासि यो - कॉर्टेज़ सामाजिक अधिकारों की मजबूत पैरोकार हैं। वह कॉरपोरेट कर कटौती को चुनौती देने वाली प्रमुख आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के लिए अधिक बजटीय आवंटन की मांग कर रही हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में जब उन्होंने बताया कि लोगों के लिए अच्छे अर्थशास्त्र का क्या मतलब होना चाहिए, तब पत्रकार एंडरसन कुपर ने उनसे पूछा, इन सबके लिए आप धन कहां से लाएंगी ?

अब भारत पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा किसानों के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की गई है। 2019 के चुनाव से पहले कई और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी कर्जमाफी की घोषणा की संभावना है, जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कृषि ऋण माफी पर सावधानी बरतते हुए कहा कि इससे ऋण अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा। बैंक ऑफ अमेरिका की निवेश बैंकिंग शाखा मेरिल लिंच ने चेतावनी दी थी कि कृषि ऋण माफी जीडीपी के दो प्रतिशत के बराबर होगी। एक सवाल बार-बार पूछा जाता है कि किसानों की कर्जमाफी के लिए पैसा कहां से आएगा। एक बार एक टीवी शो पर एंकर ने बहुत स्पष्टता से पूछा, राज्यों की तंग राजकोषीय स्थिति को देखते हुए क्या आपको यह चिंता नहीं सताती कि कृषि कर्जमाफी की होइ सारी गणना को गड़बड़ा देगी? क्या कृषि कर्जमाफी पहले से ही एक बुरी मिसाल कायम नहीं कर रही है, जिसके

आदिवासियों को उद्यम से जोड़ने की कोशिश

ऐसा नहीं था कि किसी खास घटना के बाद अचानक से मेरे मन में सामाजिक सरोकारों के प्रति झुकाव आ गया। कह सकते हैं कि कई घटनाएँ हैं, जिनसे वास्तुतः पड़ने के बाद मैंने सामाजिक विकास के क्षेत्र में आने का फैसला किया था। लखनऊ और दिल्ली से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद मैं दिल्ली के एक एनजीओ से जुड़ गईं। दिल्ली में मैंने कई वर्षों तक विभिन्न तरह के सामाजिक काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे महानगरीय परिधि से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर कुछ करना होगा। संतुष्टि की तलाश में मैंने दिल्ली छोड़कर अपने कुछ साथियों की मदद से एक संस्था की स्थापना की, जिसका मकसद था- ग्रामीण प्रबंधन व पर्यावरण विकास। नीलगिरि के इलाके को हमने अपनी कर्मभूमि चयनित किया। हमारे इस चयन का आधार था, वहां रह रहे आदिवासियों की उपेक्षा। बीती सदी के आखिरी दशक में वहां के लोग शेष दुनिया से कई दशक पीछे के हालात में रह रहे थे।

हमारी संस्था ने वहां की पारिस्थितिकी और अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखकर विकास योजनाएँ बनाईं। पहाड़ियों के लिए सही प्रौद्योगिकी, जैव-विविधता की रक्षा व विकास और स्थानीय समुदायों समेत उनकी संस्कृति की रक्षा हमारे मुख्य विषय रहे। हमने अपने सारे कामों में इन पहलुओं को हमेशा ध्यान रखा। मैं नहीं चाहती थी कि आदिवासियों के विकास के लिए उपरोक्त किसी भी मुद्दे को दरकिनार किया जाए।

हमने लगातार प्रयास करके ऐसी जरूरी तकनीकों का विकास किया, जिनमें आधुनिकता व परंपरा का मिश्रण है। ये तकनीकें न सिर्फ उच्च गुणवत्ता की जंगली खेती के लिए कारगर हैं, बल्कि वनवासी आदिवासियों के बीच स्वतंत्र उद्यमशीलता की भावना पैदा करने में भी सक्षम हैं। पिछले दहाई दशकों से इस इलाके में काम करने के दौरान

मैंने पाया है कि जंगलों में रहने वाले इन लोगों में अपने आपसे ही प्रकृति की खुब समझ है। वह कुदरत की हर हरकत को बखूबी जानते हैं। इनके सहयोग से ही हम इनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। बिना प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाए हम इनकी मदद करना चाहते थे और इसमें सफल भी रहे। मैं शुकगुजार हूँ उन लोगों की, जिन्होंने आदिवासियों के स्वतंत्र समूह बनाकर उन्हें इस काबिल बना दिया है कि वे आज शहद जैसे कई ऐसे प्राकृतिक उत्पाद बाजार तक पहुंचा रहे हैं, जो उनकी आर्थिक आजादी के लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसे समय में जब भारत और दुनिया भर में तमाम तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि वे अपनी किसी भी योजना में आदिवासियों और ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। ये ऐसे समुदाय हैं जिनके लिए जंगल और पानी प्राथमिक महत्व रखते हैं। न केवल उनकी आजीविका के लिए, बल्कि उनकी संस्कृति के लिए भी और इसलिए उन्हें वास्तव में सशक्त बनाने के लिए संवेदनशील विकास प्रक्रियाओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अपने इस सफर के लिए मुझे 2013 में प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के बाद मेरी सामाजिक जिम्मेदारी पहले से और ज्यादा हो गई है। मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ कि नीलगिरि बायोस्फियर रिजर्व में विकास न सिर्फ टिकाऊ हो, बल्कि वह किसी भी विनाश का कारण न बने।

विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

अब नए सुधारों की उम्मीद

उम्मीद है कि सरकार एक प्रभावी जीएसटी प्रणाली के तहत कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनाएगी और प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत वेंतनभोगी तथा छोटे आयकरदाताओं को राहत देगी, कर संग्रह की लागत कम करने पर विचार करेगी।



जयंतिलाल भंडारी

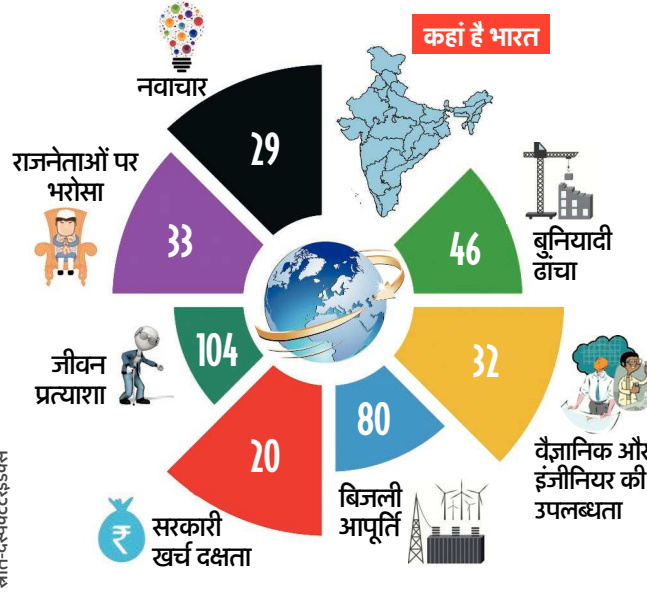
बात उभरकर सामने आ रही है कि जीएसटी भारत के लिए लाभप्रद है, लेकिन उपयुक्त क्रियान्वयन के अभाव में इसका लाभ अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाया। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की दुर्लाल सुगम हुई और टैक्स भी एक समान हुए। जीएसटी को कारगर बनाने के लिए 28 फीसदी की श्रेणी खत्म की जानी चाहिए और 12 और 18 फीसदी की दर का विलय कर एकल मानक दर की जानी चाहिए। वर्ष 2019 में जीएसटी सरलीकरण के बाद उद्योग-कारोबार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में भारत की कई उपलब्धियां रेखांकित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 2018 में भारत को 190 देशों की सूची में 77वां स्थान दिया गया। यह

रैंकिंग रिपोर्ट 2019 में बढ़ सकती है। यह विव्बंडा ही है कि वेंतनभोगी वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के लोग अच्छी कमाई रखते हुए भी आयकर नहीं देते हैं। यद्यपि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कुछ मुश्किलें बढ़ीं, लेकिन आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी। जिस तरह मैक्सिको ने डिजिटल कर प्रशासन अपनाकर कर के अनुपालन में ऊंची सफलता प्राप्त की है, उसी तरह भारत में डिजिटल कर प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन-देन का विस्तृत ब्योरा दर्ज होने से अच्छे कर प्रशासन दिखाई दे सकेगा। निश्चित रूप से कर अधिकारियों को अपना काम करने के लिए सूचना तकनीक के अधिकृष्टिक इस्तेमाल की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि करदाताओं को कर अधिकारियों से न मिलना पड़े। विभाग से किसी भी तरह के सवाल-जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो सकते हैं। कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल हो, ताकि भ्रष्टाचार में कमी आए। उम्मीद है कि सरकार एक प्रभावी जीएसटी कर प्रणाली के तहत कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनाएगी और प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत वेंतनभोगी तथा छोटे आयकरदाताओं को राहत देगी और कर संग्रह की लागत कम करने के बारे में विचार करेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले खड़ी हो सकती है।

खुली खिड़की

भारत की रैंकिंग

पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग क्षेत्रों में भारत की वैश्विक रैंकिंग सुधरी है। विश्व आर्थिक मंच समेत कुछ अन्य संस्थाओं की 137 देशों की रैंकिंग में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के वैश्विक स्थान निम्न हैं।



गृहस्थ धर्म का पालन

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती अपने प्रवचनों में ईमानदारी से अर्जित अपनी आय का कुछ अंश सेवा-परोपकार आदि कार्यों में खर्च करने की प्रेरणा दिया करते थे। एक बार वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए वह एक नगर में पहुंचे। उनके प्रवचनों का श्रोताओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। अगले दिन सुबह एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करने के बाद कहने लगा, आपके प्रवचन ने मेरी ओंखें खोल दी हैं। मैंने अपनी पूरी जवानी घर-गृहस्थी के पचड़े में खर्च कर व्यर्थ गंवा दी। अब मैं सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए अपनी दुकान बेचकर वह धन आर्य समाज को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उनसे पूछा, आपके परिवार में कौन-कौन हैं? वह व्यक्ति कहने लगा, पत्नी और दो बच्चे हैं। स्वामी जी ने उसे समझाते हुए कहा, वैदिक धर्म में गृहस्थी के पालन को श्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहकर माता-पिता, पत्नी और बच्चों की देखभाल करना व्यक्ति का परम दायित्व है। अब यदि आप आवेश में आकर दुकान बेच डालेंगे, तो यह धर्म नहीं, अधर्म माना जाएगा। हां, अपनी आय का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों पर जरूर खर्च करना चाहिए। उन व्यक्ति ने गृहस्थ धर्म में रहते हुए और अपना कारोबार चलाते हुए झूठ न बोलने, अनैतिक काम न करने और अहिंसक बनने का संकल्प ले लिया। -संकलित

हरियाली और रास्ता शिक्षिका, क्लास और दिव्यांग युवती

गैस्ट टीचर बनकर आई एक नि:शक्त युवती की कहानी, जिसने शिक्षिका की धारणा को ध्वस्त कर दिया।



उस दिन मैं कॉलेज पहुंची ही थी कि मुझे बताया गया कि आज आपकी क्लास में कोई गैस्ट टीचर आने वाला है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोच लिया कि जो भी आएगा, मैं उसे ऐसे आँखें दिखाऊंगी कि वह जल्दी वापस लौट जाएगा। मैं यह सोच ही रही थी कि एक पलभी वयंगी युवती कमरे में आई। उसका नाम था लेनो जैपेनी। मैं उसे देखकर मुह बना रही थी। एक टीचर ने बताया कि यह आईएफएस अधिकाारी हैं। उन्हें शायद हमें कोई परेशानी थी। दो लोग उन्हें पकड़कर चल रहे थे। मैं भी पीछे-पीछे क्लास पहुंच गई और पीछे जाकर बैठ गई। लेनो ने बोलना शुरू किया, दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी शिक्षिका की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आपके साथ समय बिताने का मौका दिया। सबसे जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर एक बच्चे को जब पता चले कि वह देख नहीं सकती, और उसे जिंदगी भर ऐसे ही अंधेरे में रहना होगा, तो उसे कैसा लगेगा? मेरे लिए यह स्वीकार करना बेहद कठिन था कि मेरी जिंदगी हमेशा अंधेरे के साये में रहने वाली है। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि वह सुंदर-सी युवती, जिसे मैंने मन ही मन इतना कोसा, नेत्रहीन है।

लेनो बोली, मैं देख नहीं सकती। मुझे कई बार बहुत दुख होता है, पर इसमें कई फायदे भी हैं। मैं जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं से भी उतनी ही अनजान हूँ। मेरे लिए हर शिक्क मेरा दोस्त है। चाहे वह मुझे देखकर जो भी सोचे, मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक ही होता है। हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें, तो हारकर जीना छोड़ सकते हैं, जिंदगी को जीना सकते हैं, और चाहें, तो इस खूबसूरत जिंदगी को चुनौतियों के साथ अपना सकते हैं, जैसा मैंने किया। जिंदगी हर पल हमें कुछ सिखाती है। वस हमारे समझने की देर है।